

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2010

(विधानसभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के इक्सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) अधिनियम, 2010 है ।

(2) यह 07 अक्टूबर, 2010 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 4—क
का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 की धारा 4—क में, “विक्रय करने या करवाने अथवा परिवहन के लिए प्रेषण को प्राधिकृत करने” शब्दों के स्थान पर “विक्रय करने या क्रय करने अथवा परिवहन के लिए प्रेषण या प्राप्ति कारित करने या करवाने को प्राधिकृत करने वाला” शब्द रखे जाएंगे ।

2010 के
अध्यादेश
संख्यांक 7 का
निरसन और
व्यावृत्तियां ।

3. (1) हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) अध्यादेश, 2010 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विभिन्न औद्योगिक और अन्य ईकाइयों द्वारा किए गए थोक क्रय और बड़ी औद्योगिक ईकाइयों जैसे कि लोहा और इस्पात उद्योगों द्वारा हिमाचल प्रदेश से अन्य राज्यों को माल के प्रेषण से, बैरियरों पर अधिक भीड़-भाड़ हो रही है जिसने यानों के आवागमन की गति को ज़बरदस्त रूप से कम कर दिया है । यद्यपि हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 की धारा 4-क में सड़क द्वारा वहन के लिए माल के प्रेषण पर अतिरिक्त माल कर के संग्रहण करने को प्राधिकृत करने का उपबन्ध विद्यमान है, तथापि, ऐसी औद्योगिक ईकाइयों द्वारा थोक में क्रय किए जाने से बैरियरों पर अभी भी भीड़-भाड़ हो रही है और यातायात के मुक्त आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है । इसलिए बैरियरों पर अधिक भीड़-भाड़ को कम करने और यातायात के आवागमन को सुचारू करने के आशय से तथा विसंगति को भी दूर करने के लिए राजस्व और सार्वजनिक सुविधा के हित में पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4-क को संशोधित करना समीचीन समझा गया है । थोक में क्रय की प्राप्तियों पर अतिरिक्त माल कर के संग्रहण को प्राधिकृत करने से, बैरियरों पर भीड़-भाड़ कम हो जाएगी, क्योंकि प्राधिकृत व्यक्ति की ओर से और उसके लिए राज्य के भीतर माल को लाने वाले यानों को, कतार में प्रतीक्षा करनी अपेक्षित नहीं होगी ।

क्योंकि विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 में संशोधन करना आवश्यक हो गया था । इसलिए, हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश संख्यांक 7) 1 अक्टूबर, 2010 को प्रख्यापित किया गया था और जिसे 7 अक्टूबर, 2010 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था, अब उक्त अध्यादेश को नियमित विधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है ।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को बिना उपान्तरण के प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री ।

धर्मशाला:

तारीख :....., 2010.

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित होने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रवर्तित किए जाने हैं और इसलिए राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा ।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2 राज्य सरकार को सङ्क द्वारा वहन के लिए, थोक में क्रय किए गए माल की प्राप्तियों पर कर का संग्रहण करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करने को सशक्त करता है।

**THE HIMACHAL PRADESH PASSENGERS AND GOODS TAXATION
(AMENDMENT) BILL, 2010**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955 (Act No. 15 of 1955).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty- first Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation (Amendment) Act, 2010.

Short title and commencement.

(2) It shall be deemed to have come into force on 7th day of October, 2010.

2. In section 4-A of the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955, for the words “selling or causing or authorising to cause despatch”, the words “selling or purchasing or causing or authorizing to cause despatch or receipt” shall be substituted.

Amendment of section 4-A.

3. (1) The Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation (Amendment) Ordinance, 2010 is hereby repealed.

Repeal of Ordinance No. 7 of 2010 and savings.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The bulk purchases made by various industrial units and others and the despatch of goods from Himachal Pradesh to other States by the big Industrial Units, such as Iron and Steel Industries have been adding to congestion at the Barriers which drastically curtail the speed of movement of vehicles. Though there exists a provision under section 4-A of the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955 to authorise for collection of Additional Goods Tax on despatch of goods for carriage by Road, however, the bulk purchases being made by such Industrial Units are still creating congestion at Barriers and free flow of traffic is being hampered. Therefore, in order to decongest the Barriers and to make movement of traffic smooth and also to remove the anomaly, it is considered expedient in the interest of revenue and public convenience to amend section 4-A of the Act ibid. The authorisation to collect additional Goods Tax on receipt of bulk purchases will help in decongesting the Barriers as Vehicles bringing Goods inside the State for and on behalf of authorised person will not be required to wait at Barriers.

2. Since, the Legislative Assembly was not in session and amendment in the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955 had to be made urgently. Therefore, the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation (Amendment) Ordinance, 2010 (H.P.Ordinance No. 7 of 2010) was promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India by the Governor of Himachal Pradesh on 1st October, 2010, which was published in Rajpatra, Himachal Pradesh on 7th October, 2010. Now, the said Ordinance is required to be replaced by a regular legislation.

3. This Bill seeks to replace the said Ordinance without modification.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

DHARAMSHALA :

The2010.

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill when enacted are to be enforced through the existing Government machinery and there will be no additional expenditure from the State exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 2 of the Bill seeks to empower the State Government to authorise a person to collect tax on receipt of goods purchased in bulk for carriage by road. This delegation is essential and normal in character.
